

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त R

अब हर सच होगा उजागर



केंद्र सरकार की कोविड को लेकर राज्यों को चेतावनी

15 अगस्त पर बड़ी सभाएं करने से बचें



नई दिल्ली। देश में रोजाना कोविड-19 के औसतन 15,000 से अधिक मामले सामने आने के बीच केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कार्बड़ी सभा नहीं हो और सभी लोग कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान चलाने और स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी के माध्यम से इन्हें स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक प्रखण्ड और महीने भर तक जारी रखने को कहा है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस-शिवसेना में तकरार



कांग्रेस बोली- शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी नहीं, हम हालात के चलते साथ आए

मुंबई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी गठबंधन (एमवीए) सरकार को गए डेढ़ महीना भी नहीं बीता है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में अभी से तकरार दिखने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि उद्घव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। जिस समय शिवसेना से गठबंधन हुआ था, उस दौरान परिस्थितियां अलग थीं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

महाराष्ट्र के 608 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीख जारी

18 सितंबर को होगा चुनाव



शायद मुझमें काबिलियत नहीं, शिंदे कैबिनेट में जगह न मिलने पर नाराज पंकजा मुंडे का दर्द



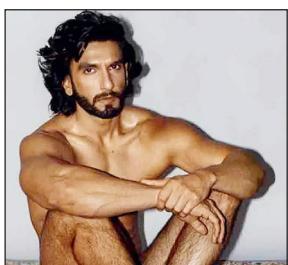
मुंबई हलचल / संवाददाता
मुंबई। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र मन्त्रिमंडल के हालिया विस्तार के दौरान उन्हें कैबिनेट में स्थान नहीं मिलने पर बृहस्पतिवार को कहा कि शायद उनमें इसके लिए 'पर्याप्त योग्यता' नहीं है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

मुंबई हलचल / संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के 51 तालुकों की 608 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों समेत सरपंचों का भी चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। चुनाव 18 सितंबर 2022 को होगा। आचारसंहिता लागू हो गई है। काउंटिंग 19 सितंबर को किया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार, 12 अगस्त राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त यू.पी. एस मदान ने की। (शेष पृष्ठ 3 पर)

न्यूड फोटोशूट के समें रणवीर सिंह से होगी पूछताछ

मुंबई पुलिस ने एक्टर को बुलाया, महिलाओं की भावनाएं आहत करने का था आरोप



मुंबई। न्यूड फोटोशूट मामले में रणवीर सिंह को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मॉडिया रिपोर्टर्स के अनुसार, एक्टर को 22 अगस्त के दिन हाजिर रहने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर रणवीर के मुंबई स्थित घर पहुंचे थे। दरअसल, रणवीर पर मुंबई के एक एनजीओ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन पर आरोप लगाया गया था कि रणवीर ने सोशल मीडिया पर न्यूड फोटोज शेयर कर महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। एनजीओ ने कहा था कि एक्टर ने अपनी न्यूड फोटोज से महिलाओं की भावनाओं को डेस पहुंचाई है और उनका अपमान किया है। इसलिए ट्रिवटर और इंस्टाग्राम से उनकी फोटो हटाई जाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि रणवीर को गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 509, 292, 293 आईटी एक्ट के सेक्षण 67ए के तहत केस दर्ज हुआ है।

हमारी बात**अपराधी नेताओं
को सजा?**

आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी मजेदार याचिका पर बहस चल रही है। उसमें माग की गई है कि जिस भी विधायक या सांसद को आपराधिक मामलों में सजा दी गई हो, उसे जीवन भर के लिए राजनीति से बाहर क्यों नहीं किया जाए? अभी 1951 के जन-प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक यदि किसी नेता को सजा मिलती है तो छह वर्ष तक वह न तो कोई चुनाव लड़ सकता है और न ही किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी बन सकता है। छह साल के बाद वह याहे तो फिर दनदना सकता है। अब यदि ऐसे नेताओं पर जीवन भर का प्रतिबंध लग जाए तो क्या हमारी राजनीति का शुद्धिकरण नहीं होगा? ऐसे कड़े प्रतिबंध के डर के मारे नेता लोग अपराध आदि करने से क्या बचे रहना नहीं चाहेंगे? इस याचिका को पेश करनेवाले अश्विन उपाध्याय का तर्क है कि यदि एक पुलिसवाला या कोई सरकारी कर्मचारी किसी अपराध में जेल भेज दिया जाता है तो उसकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या नहीं? जहां तक नेता का सवाल है, उसके लिए राजनीति सरकारी नौकरी की तरह उसके जीवन-यापन का एक मात्र साधन नहीं होती है। वह तो जन-सेवा है। उसका शौक है। उसकी प्रतिष्ठा पूर्ति है। राजनीति से बाहर किए जाने पर वह भूखा तो नहीं मर सकता है। इस तर्क का समर्थन भारत के चुनाव आयोग ने भी किया है लेकिन चुनाव आयोग स्वयं तो किसी कानून को बदल नहीं सकता। उसके पास नया कानून बनाने का अधिकार भी नहीं है। ऐसे में सरकार चाहे तो वह कुछ ठोस पहल कर सकती है। वह संसद में प्रस्ताव लाकर ऐसा कानून जरूर बना सकती है लेकिन कोई भी सरकार ऐसा कानून क्यों बनाना चाहेगी? यदि वह ऐसा कानून बना दे तो उसके कई बड़े-बड़े नेता राजनीति से बाहर हो जाएंगे। देश के अनेक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक साधारण अपराधियों की तरह जेल की हवा खा चुके हैं और कई तो अभी जेल में ही सड़ रहे हैं। मैं उनके नाम यहां नहीं दिना रहा हूँ। यदि उनके विरुद्ध वैसा कानून बन गया तो देश की राजनीति में भूकंप आ जाएगा। यह भी ठीक है कि कई नेताओं की उनकी विरोधी सरकारों ने बनावटी आरोपों के आधार पर सीखचों के पीछे धकेल दिया था। इसके अलावा यदि सत्तारूढ़ पार्टी अपने किसी प्रबल विरोधी नेता को राजनीति से बाहर करने के लिए इस कानून का सहारा ले लेंगी तो कोई आश्वय क्यों होगा? इसीलिए इस याचिका पर फैसला देते हुए अदालत को कई मुहूँ पर विचार करना होगा। बीच का रास्ता यह भी हो सकता है कि राजनीति से अपराधियों के निर्वासन की अवधि 6 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। 10 साल में तो अच्छे-खासे नेताओं की भी हवा खिसक जाती है। राजनीति को अपराधियों से मुक्त करना बहुत जरूरी है लेकिन वास्तविक पश्चात्ताप करनेवालों को दुबारा मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है?

हम करें तो सशक्तिकरण आप करें तो रेवड़ी!

यह नहीं हो सकता है कि एक पार्टी की सरकारें नागरिकों को जो सुविधाएं दें उनको सशक्तिकरण माना जाए और दूसरी पार्टियों की सरकारें द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को रेवड़ी कल्वर कहा जाए। इसका फैसला और परिभाषा यह ध्यान में रख कर तय की जानी चाहिए कि निश्चित रूप से नागरिकों को निःशुल्क सुविधाएं देने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है लेकिन वह सरकारी खजाना भी नागरिकों की मेहनत की कमाई और उनके टैक्स से ही भरता है। अगर भारत एक अविकसित देश है और करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो उन्हें किसी भी तरह से वो सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और यह सरकारों की जिम्मेदारी है।



मुफ्त की चीजें बांटने या 'रेवड़ी कल्वर' की बहस थम नहीं रही है। उलटे यह बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस पर रोक लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें सर्वोच्च अदालत का कहना था कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों, चुनाव आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ साथ सभी हितधारकों को शामिल किया जाए। बाद में चुनाव आयोग ने एक हलफानामा देकर अपने को इससे अलग करने को कहा क्योंकि वह एक संवैधानिक निकाय है और वह पार्टियों व दूसरी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के साथ किसी समिति में नहीं रह सकती है।

असल में चुनाव आयोग इस बात से चिंतित है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और उसके मीडिया रिपोर्टिंग से यह धारणा बन रही है कि वह इस मामले को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। परंतु सवाल है कि चुनाव आयोग गंभीर होकर भी क्या कर सकता है, जबकि इस बात की कोई परिभाषा ही तय नहीं है कि किस चीज को 'मुफ्त की चीज बांटना' या 'रेवड़ी कल्वर' कहेंगे? भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है इसलिए यहां नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। सो, सबसे पहले तो यह तय करना होगा कि बुनियादी सुविधाएं क्या हैं, जिन्हें उपलब्ध कराना है और मुफ्त की सुविधाएं क्या हैं, जिन्हें नहीं उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा कि 'सशक्तिकरण' और 'रेवड़ी कल्वर' में बहुत बारीक फर्क है। उनके कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है वह नागरिकों का 'सशक्तिकरण' करना है लेकिन विपक्ष जो सुविधाएं दे रहा है या देने की

घोषणा कर रहा है वह 'रेवड़ी कल्वर' है।

यह सचमुच बहुत बारीक फर्क है और इसे राजनीति के नजरिए से देख कर परिभाषित करना हमेशा जोखिम भरा काम होगा। उसमें गलती की गुंजाइश रहेगी। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार देश के किसानों को हर महीने पांच सौ रुपए 'सम्मान निधि' देती है। इसे साल में तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपए के हिसाब से दिया जाता है। यह किसानों को उनके सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। इसी तरह आम आदमी की पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में हर वरस्त महिला को एक हजार रुपए महीना देने का बादा किया था, जिसे उनकी राज्य सरकार पूरा कर रही है। अब उन्होंने यहीं बांदा गुजरात में किया है। अरविंद केजरीवाल यह काम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से किसान मुश्किल ज्येल रहे हैं और हाशिए में हैं वैसे ही महिलाएं भी तमाम बातों के बावजूद वंचित समूह में आती हैं। उनको अगर सशक्त बनाने के लिए नकद दिया जाता है तो वह किसानों को दिए जाने वाले सम्मान निधि से अलग नहीं हो सकता है। दोनों या तो सशक्तिकरण हैं या दोनों रेवड़ी कल्वर का हिस्सा हैं।

इसमें संदेह नहीं है कि कई राज्य सरकारें एक सौ से लेकर तीन सौ यूनिट तक बिजली फ्री दे रही हैं, जिनकी वजह से बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों से लेकर उत्पादन करने वाली कंपनियों और कोयला कंपनियों की स्थिति पर नकारात्मक असर हुआ है। उनके भुगतान में दोरी हुई है और उनका कर्ज बढ़ा है। लेकिन यह सिर्फ इस वजह से नहीं है कि सरकारों लोगों को सस्ती या मुफ्त की बिजली दे रही है। यह सरकारों की कमी है कि वे बिजली कंपनियों के भुगतान में देवी कर रही हैं। सरकारों वंचित या आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को सस्ती या मुफ्त की बिजली दे रही है तो उसकी

वसूली मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग से कर रही है। जिन घरों में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां फिल्स्ट चार्ज से लेकर बिजली के चार्ज और टैक्स आदि बहुत ज्यादा होते हैं, जिनसे सरकार के खजाने में पैसा आता है। ऊपर से सरकारें इसके लिए सब्सिडी तय करती हैं। अगर वे समय पर भुगतान करें तो बिजली कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं होगा। भारत में आजादी के बाद से निःशुल्क या सस्ती कीमत पर राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था रही है। पीने का साफ पानी निःशुल्क उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। दशकों से सरकारें सस्ते आवास देती रही हैं। उसी में दिल्ली की सरकार ने सात-आठ साल पहले सस्ती या मुफ्त बिजली जोड़ दी। आजादी के बाद से ही केंद्र में चाहे जिसकी सरकार रही होती रही है। भारत चेचक से लेकर मलेरिया, हैजा या पोलियो जैसी बीमारियों से मुक्त हुआ है तो उसका कारण निःशुल्क टीकाकरण है। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार ने कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगवाई तो उसने मुफ्त में टीका लगवाने का ऐसा प्रचार किया, जिसकी मिसाल नहीं है। इसके लिए पूरे देश से धन्यवाद भी आमंत्रित किया गया, जैसे भाजपा के एक सांसद ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को हाफ़की फंडल में खाना दे रहे हैं तो उनका धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सो, पिछले आठ साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सम्मान निधि, प्री फंड के खाने या प्री फंड की वैक्सीन का ज्यादा प्रचार हुआ है। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके खिलाफ निर्णयिक जंग लें दी है।

तभी जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाओं को शामिल करने या न्यायपालिका से कोई फैसला कराने से पहले सरकार पहल करे और सभी पार्टियों को बुला कर इस पर विचार करे। इसकी एक सीमा तय करे कि देश के नागरिकों को क्या सुविधा देना सशक्तिकरण की श्रेणी में आएगा और किस चीज को प्री फंड की चीज माना जाएगा। यह नहीं हो सकता है कि एक पार्टी की सरकारें नागरिकों को जो सुविधाएं दें उनको सशक्तिकरण माना जाए और दूसरी पार्टियों की सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को रेवड़ी कल्वर कहा जाए। इसका फैसला और परिभाषा यह ध्यान में रख कर तय की जानी चाहिए कि निश्चित रूप से नागरिकों को निःशुल्क सुविधाएं देने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है लेकिन वह सरकारी खजाना भी नागरिकों की मेहनत की कमाई और उनके टैक्स से ही भरता है। अगर भारत एक अविकसित देश है और करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो उन्हें किसी भी तरह से वो सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और यह सरकारों की जिम्मेदारी है।

आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शिवसेना की पूर्व नगरसेवक सुधीर भगत द्वारा तिरंगा झंडा वितरण किया गया

संवाददाता/समद खान

मुंबई। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शिवसेना के पूर्व नगरसेवक सुधीर भगत द्वारा तिरंगा झंडा वितरण किया गया दरअसल आपको बताते चलें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करना है देश के पंतप्रधान मोदी जी द्वारा अभियान के तहत 11 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आहान किया गया है इसी के चलते सभी संस्थाओं एनजीओ द्वारा देशवासियों से अपील की जा रही है की अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर लगाएं वहीं दूसरी ओर शिवसेना के पूर्व नगरसेवक सुधीर भगत द्वारा संजय नगर परिसर में तिरंगा अभियान चलाया गया जिसमें उनके द्वारा सभी वर्ग के लोगों निंदू मुस्लिम सभी समुदाय के घरों में दुकानों में मस्जिदों में जाकर तिरंगा झंडे का वितरण किया गया इस



अवसर पर पत्रकरों से बात करते हुए सुधीर भगत ने बताया कि अभी 75 वर्ष आजादी को पूरे हो गए हैं और जो आजादी का अमृत महोत्सव का अभियान चलाया जा रहा है वह बड़ी खुशी की बात है जिसके चलते हर घर में तिरंगा नजर आएगा उन्होंने आजादी में शहीद हुए स्वतंत्र सेनानियों चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह मौलाना आजाद की याद ताजा करते हुए बताया कि आज उन्होंने

लोगों के बजह से हमारे बाल बच्चे चैन की सांस ले रहे हैं उनके द्वारा देश के प्रति दिया गया बलिदान को कभी इतिहास द्वारा भुलाया नहीं जा सकता आज देश को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं हम लोगों को भी चाहिए कि जिस तरह से हम ईंट और दीवाली की खुशी मनाते हैं उस तरह से देश के आजादी का दिन स्वतंत्र दिवस की खुशी बनाएं उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को आजादी के अमृत

महोत्सव की शुभकामनाएं दी और बताया कि हमारी संस्था हेलिंग हैं इस द्वारा 400 लोगों को तिरंगा झंडा वितरण किया गया और लोगों से अपील की है स्वतंत्र दिवस की खुशियां बढ़े धूमधाम से मनाएं उनके साथ उपस्थित सूफी साहब ने बताया कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे में भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं है हम लोग हमेशा मिलजुल कर रहते हैं मुसलमान ने हमेशा जोड़ा है तो इने की कोशिश कभी नहीं की है लेकिन कुछ लोग हैं जो भेदभाव पैदा करके आपस में बुराई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को जातिवाद हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग कभी ऐसा होने नहीं देंगे उन्होंने अपने पड़ोसी मराठा व्यक्ति की मिसाल देते हुए बताया कि वह व्यक्ति कहता है सूफी साहब आप महान हैं क्योंकि हम लोग हमेशा उसके दुख और सुख में हमेशा खड़े रहते हैं।

कम कीमत पर ऑडी देने का झांसा देकर डॉक्टर को ठगा, 34 लाख लेने के बाद भी नहीं दी कार

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां कांडिवली पश्चिम के बाबासाहेब अंडेक्टर अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर को एक कार डीलर ने ठगी का शिकार बनाया है। जिसने कम कीमत में ऑडी कार का झांसा देकर बेचने की पेशकश की थी। वहाँ, डीलर ने डॉक्टर से बादा किया था कि वह उसे 63 लाख रुपये की ऑडी 34 लाख रुपये में बेचेगा। लेकिन अगस्त से सितंबर 2021 के बीच कार डीलर ने डॉक्टर से 34 लाख ले लिए, मगर, गाड़ी सौंपी नहीं। हालांकि, इस मामले में कांडिवली पुलिस का कहना है कि, आरोपी डीलर ने डॉक्टर को 9 लाख रुपये लौटा दिए, बकाया रकम में से कुछ के चेक बाउंस हो गए हैं, फिलहाल मामले



की जांच की जा रही है। दरअसल, मुंबई के कांडिवली पश्चिम में डॉ बाबासाहेब अंडेक्टर नगर अस्पताल में तैनात डॉक्टर बोरिवली पश्चिम के रहने वाले डॉ रोशन झा (34) ने अपने मित्र से पता चला कि उसने ऑडी ए-6 को 25 लाख रुपये में खरीदा है। जिसे उसने मलाद पश्चिम के रहने वाले कार डीलर प्रशांत चौधरी से ऑडी कार खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का भुगतान किया।

किया था, जबकि कार की शोरूम कीमत 63 लाख थी। ऐसे में उसने कार खरीदने के लिए डीलर से मिलने की बात कहीं। कांडिवली पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर से डीलर ने 25 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसी तरह से आरोपी ने कई लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कई लोगों को कम कीमत पर कार दी थी, जिसके बाद लोगों से रुपये लेकर उन्हें कार नहीं सौंपी। इसी दौरान पीड़ित डॉक्टर को कार डीलर 34 लाख रुपये में ऑडी-ए-6 देने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए उसने आरटीओ के एक एजेंट से भी संपर्क किया, जहां उसने अपनी पसंद के एक फैसी नंबर के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान किया।

दरगाह दर्शन के लिए गए दो युवक मीठी नदी में डूबे, एक की मौत, दूसरा लापता



मुंबई। मुंबई के माहिम कॉस्ट में मीठी नदी में दो युवकों के डूबने की खबर है। दोनों युवक कुर्ला से माहिम दरगाह दर्शन के लिए गए थे। देर रात घर लौटते समय कुछ देर के लिए दोनों माहिम कॉस्ट के खाड़ी पास खड़े थे। तभी एक युवक का पैर पानी के बहाव के चलते फिसला और वह नीचे गिर गया। इसी बीच उसे बचाने दूसरा युवक कूदा, लेकिन मीठी नदी के बहाव में दोनों डूब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई उसका शव बरामद किया गया है। जबकि दूसरे की तलाश जारी है। जावेद शेख नामक व्यक्ति का शव फायर ब्रिगेड ने बरामद कर लिया है। वहीं लापता

दूसरे युवक आशिफ की तलाश जारी है। इससे पहले भी प्रदेश में डूबने की घटनाएं सामने आती रही हैं। पुणे जिले के चकन इलाके में पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबकर तीन नाबालिंग भाई-बहनों की मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि चकन के समीप अंवेथन गांव में एक खेत पर पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान चार से आठ साल के इन बच्चों की डूबकर मौत हो गयी। उन्होंने कहा कि राकेश किशोर दास (पांच), उसका भाई रोहित (आठ) और बहन शवेता (चार) गड्ढे में उतर थे जिसे उनके पिता ने खेत पर खोदा था और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था।

(पृष्ठ 1 का समाचार)

केंद्र सरकार की कोविड को लेकर राज्यों को चेतावनी मंत्रालय ने कहा कि एहतियात के तौर पर कोविड-19 के खिलाफ, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह जरूरी है कि कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 16,561 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,23,557 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीज 1,23,535 हैं। मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से 49 लोगों की मृत्यु होने से मुतक संख्या बढ़कर 5,26,928 हो गई है। मौत के इन 49 मामलों में 10 लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम आंकड़ों का पुनःमिलान करते हुए केल ने संक्रमण से हुई मौत की सूची में डाले हैं। यह मंत्रालय ने सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने को भी कहा है। दिल्ली में कोरोनावायरस के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। अगस्त के शुरूआती 10 दिनों में ही कोरोना के करीब 20 हजार मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में संक्रमण दर एक अगस्त को 11.41 फीसदी थी और 822 मामले मिले थे। जबकि अब संक्रमण दर 20 फीसदी तक पहुंच गई है। दो अगस्त को 1506 मामले आए थे जबकि 3 अगस्त को संख्या 2000 पर कर गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की बजह से लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ के पार जा चुकी है। 19 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार एक करोड़ का आंकड़ा पार किया था। इसके बाद 4 मई 2021 को कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के मामलों ने चार करोड़ का आंकड़ा हुआ था।

महाराष्ट्र के 608 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीख जारी

मदान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 17 मई 2022 के आदेश के मुताबिक जिन इलाकों में बरसात की बजह चुनाव प्रभावित होने की संभावनाएं नहीं हैं, उन इकायावान तालुके के छह सौ आठ ग्राम पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि जिन ग्राम पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है, वहां ज्यादा बरसात या बाढ़ या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा से जुड़े हालात पैदा हों तो इस बारे में चुनाव आयोग को वे तत्काल रिपोर्ट भेजें। घोषित किए गए चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक संबंधित तहसीलदार 18 अगस्त 2022 को चुनाव से संबंधित नोटिस पब्लिश करेंगे। नामांकन का काम 24 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरा किया जा सकेगा। 27,28 और 31 तारीख को सार्वजनिक छुट्टियों की बजह से नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद नामांकनों की जांच 2 सितंबर 2022 को होगी। नाम वापस लेने की आवधिरा तारीख 6 सितंबर के दोपहर 3 बजे तक होगी। मतदान 18 सितंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। मतगणना 19 सितंबर को होगी। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश में तय किए गए अनुपात में इस चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीटें तय की गई हैं।

महाराष्ट्र में सरकार जाते ही कांग्रेस-शिवसेना में तकरार

पटोले ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति पर भी नाराजी जताई। उन्होंने कहा कि यह पद कांग्रेस को दिया जाना चाहिए था। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर दोनों पद आपस में बांट लिए हैं। शिवसेना ने हाल ही में अपनी पार्टी के अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। पटोले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना यह कदम उठाया गया। पटोले ने कहा- विधानसभा में एनसीपी की ओर से विपक्ष का नेता बनाया गया, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया है। पटोले ने कहा कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछे बिना फैसला लिया गया। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस मामले पर शिवसेना से बात करने को तैयार हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते, तो यह उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। यह हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है।

शायद मूर्खमें काबिलियत नहीं...

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विस्तार के तहत पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के नौ मंत्रियों और उनके बीजेप

बिहार में दिनदहाड़े पत्रकार की गोली मारकर हत्या

पत्रकारों पर हो रहे हमले बहुत ही चिंताजनक - इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन

संवाददाता/सैम्यद अलताफ हुसैन
बिहार, जमुई। इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव मो. जहांगीर ने कहा कि उन्होंने प्रदेश व देश में आये दिन पत्रकारों की हत्या, हमले और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकें जाने की मांग रख्या था केंद्र सरकार से की मार सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करता है। देश में पत्रकार उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इस घटना की भी इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन (इए) निंदा करती है। और जल्द से जल्द हत्यारे गिरफ्तार होने चाहिए। पत्रकार को खुले आम बाइक सवार शूटर्स ने मारी पांच गोलियां बिहार के जमुई में अपराधियों



बूतक पत्रकार गोकुल यादव

ने दिनदहाड़े एक दैनिक अखबार के पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने पत्रकार को सीने और सिर में पांच गोलियां मारी हैं। घटना जिले सिमुलतल्ला थाना इलाके की है। बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार को घर से एक किलोमीटर की दूरी गोपलामारण गांव के पास गोली मारी। मृतक पत्रकार का नाम गोकुल यादव है जो सिमुलतल्ला इलाके के लीलावरण गांव का रहने वाला था। बीएसपीएस बिहार इकाई की ओर से जमुई के वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिन्हा दिवंगत पत्रकार के आवास पहुंचे। इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन और बीएसपीएस बिहार इकाई ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।



शाहपुरा में हिंदू जागरण मंच आज मनाएगा अखंड भारत संकल्प दिवस

मुंबई हलचल / भैरु सिंह राठौड़

राजस्थान। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में 13 अगस्त को हिंदू जागरण मंच द्वारा अखंड भारत दिवस मनाने का संकल्प कार्यक्रम किया जाएगा हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक हनुमान थाकड़ ने बताया कि 13 अगस्त को साए 6:15 पर त्रिमूर्ति चौराहा शाहपुरा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा 1100 दीपक जलाकर फिर से भारत को अखंड बनाने का संकल्प लिया जाएगा इसमें हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीण, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, शाहपुरा नगर वासी, वरिष्ठ नागरिक, पूर्व सैनिक, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। उक्त जानकारी क्षेत्रीय पत्रकार मोनू छोपा ने राजस्थान संपादक भैरु सिंह राठौड़ को दी है।

मध्यप्रदेश में कलेक्टरों के विरुद्ध पत्रकारों ने खोला नोर्मा, जबरदस्त आक्रोश

तुगलगी फरमान को लेकर प्रशासन और पुलिस से हुआ था पत्रकारों का पंगा, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया

मुंबई हलचल / भैरु सिंह राठौड़ / मुकेश शर्मा

राजस्थान। फिले 7 दिनों से लगातार पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे पत्रकारों ने एकत्रित होकर मुरैना कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अपर आयुक्त राणेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा साथ ही सूबेदार मलखान सिंह को बर्खास्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक के नाम पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागारी को ज्ञापन सौंपा और पांचवे दिन शाम को मशाल जलूस निकाल कर मुरैना कलेक्टर की कार्यप्रणाली के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जात हो कि ग्वालियर और मुरैना नगर में नगर निगम के सभापति चुनाव के दौरान मुरैना कलेक्टरों ने तुगलगी फरमान जारी कर पत्रकारों को परिसर में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया था ग्वालियर में तो पत्रकार अपमान सहन कर गये पर मुरैना में मामला तूल पकड़ गया और पत्रकारों ने गेट पर अपने कार्ड लटका कर विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध करना शुरू कर दिया गया था ग्वालियर में तो पत्रकारों से अभद्रता कर धक्का मुक्की कर दी। उसके बाद समस्त पत्रकारों ने सूबेदार मलखान सिंह को बर्खास्त कर मुरैना कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया जो दिन प्रतिदिन उत्तर स्वरूप लेता जा रहा है और पिछले सात दिनों से प्रशासनिक खबरों को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। केवल जनहित की खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। पत्रकारों में अक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पत्रकारों के आंदोलन को प्रदेश भर के पत्रकारों के जनसमर्थन के साथ अन्य समाज संवियों, नेताओं, संगठनों का समर्थन मिलता जा रहा है।

मुरैना कलेक्टर कार्तिकेयन ने की न्यायालय के निर्देशों की अवामानना।

जौरा शहर के मध्य स्थित सरकारी मिल्कियत की बेशकीमती औकाफ भूमि की आपने राजनीतिक प्रभाव से नोईयत बदलबाकर उस पर दुकानें बनाए एवं उनके



विक्रय में अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले में मुरैना कलेक्टर को इंफेसला क्यों नहीं कर रहे? दबाव में या प्रभाव में? वह मामला कलेक्टर न्यायालय में विगत लगभग 3 वर्षों से लंबित है। जबकि मामले का निराकरण के लिए उच्च न्यायालय कुछ माह पूर्व ही कलेक्टर मुरैना को निर्देश दे चुका है। उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का क्रमांक 24/2 की भूमि सर्वे क्रमांक 422 करबे के मध्य स्थित उपय बेशकीमती भूमि है यह भूमि संवत् 2026 से 2029 तक राजस्व अभिलेखों में औकाफ भूमि मिल्कियत सरकारी के रूप में दर्ज थी। उल्लेखित भूमि को तत्कालीन मार्केटिंग सोसायटी अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक द्वारा राजस्व अधिकारियों से संठारांठ कर राजस्व अभिलेखों में मार्केटिंग सोसायटी की मिल्कियत के रूप में अंकित करा दिया है। पूर्व विधायक जोरा महेश दत्त मिश्र द्वारा उच्च न्यायालय में रिप्टीशन दायर की। पिटीशन निराकरण करते हुए न्यायालय ने पिटीशन कर्ता को कलेक्टर कार्यालय भेजा लेकिन न्यायालय के आदेश को भी कलेक्टर महोदय नहीं माना और मामला पैडिंग रहा।

मुरैना कलेक्टर कार्तिकेयन से पूर्व में भी हो चुका है पत्रकारों का विवाद।

नगरीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया के दैरान शासन के

आदेश पर मुरैना कलेक्टर द्वारा न्यू कलेक्टर परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था लेकिन पोलिंग बूथ पर भारी व्यवस्थाओं का बखान करने वाले कलेक्टर साहेब भीषण गर्मी में की गई प्रेस वार्ता में पानी तक की व्यवस्था करना भूल गए। जिस पर कुछ पत्रकार साथियों ने कलेक्टर साहेब के चैंबर में जाकर सवाल जवाब शुरू कर दिए कि जब यहां पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है तो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्था करोगे। इस पर कलेक्टर साहेब ने उन पत्रकारों की जनसंपर्क अधिकारी से कुंडली मांगना शुरू कर दी और जनसंपर्क अधिकारी को सवाल जवाब करने वाले पत्रकारों के निर्वाचन कार्ड न बनाने की हिदायत दे डाली जिसका शोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ तब जाकर पत्रकारों के निर्वाचन पास जारी हुये।

पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र को जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है, कहा है कि 'पन्ना कलेक्टर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें पद से हटा देना चाहिए।' जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर संजय

कुमार मिश्र को फटकार लगाने के साथ कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। हाल में पन्ना की गुनौर जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अफसरों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। विंग 27 जुलाई को हुए जनपद पंचायत गुनौर में उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता परमानंद शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस का तुगलगी फरमान है कि जिले के समस्त पत्रकार जिला जनसंपर्क कार्यालय सहित भोपाल जनसंपर्क कार्यालय में अपनी फाइल जमा करेंगे तो साहेब भिंड में अब कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे कौन पत्रकार है कौन नहीं? कलेक्टर साहेब कोई संवादाता मध्यप्रदेश से बाहर छपने बाले अखबार में काम करता है उसका क्या? अगर अखबार की कांपी मांगयेगा उसके पैसे आप दोंगे? थोड़ा प्रेस एक्ट पढ़ो? जबकि प्रेस एक्ट में भारतीय संविधान के आर्टिकल के अनुसार धारा 19ए के तहत देश का प्रत्येक नागरिक पत्रकार ही है। पत्रकार का मतलब जो व्यक्ति किसी भी समाचार पत्र को सूचना आदान प्रदान करने का कार्य कर रहा हो। तो क्या प्रत्येक नागरिक आपके हिटलर शाही फरमान के तहत फाइल जमा करेगा?

डेमोक्रेटिक प्रेस कलब ने उठाये सवाल?

डेमोक्रेटिक प्रेस कलब के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने प्रदेश में पत्रकारों की प्रताड़ना पर सवाल उठाते हुए सरकार से सीधी ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है श्री शर्मा ने बताया कि संगठन जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा। (जैसा विरिष पत्रकार मुकेश शर्मा ने राजस्थान संपादक भैरु सिंह राठौड़ को बताया)

शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर मिलते हैं ये 7 संकेत

शुगर लेवल बढ़ने के संकेत : शरीर में शुगर लेवल का बढ़ना या कम होना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शुगर लेवल अनकंट्रोल होने पर शरीर के कई ऑग्नर्स डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए शरीर में शुगर लेवल का सही होना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो ज्यादातर यह परेशानी लगातार काम और स्ट्रेस हो सकता है। मार्किट में मिलने वाली कई चीजों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर पाई जाती है, जिसे आप रोजाना लेते हैं। इसके अलावा घर पर बने भोजन में भी कम से कम 12 चम्पच चीजों की मात्रा होती है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी और लक्षण न पता होने के कारण वो इस इसके प्रति सतर्क नहीं हो पाते लेकिन कुछ साधारण संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि आप बहुत अधिक मात्रा में शुगर ले रहें हैं।

शरीर में शुगर का स्तर 70 से 110 मिलीग्राम होना चाहिए। शुगर लेवल 110 से 125 तक होने पर भी घबराने की बात नहीं है लेकिन लेवल इससे ज्यादा बढ़ने पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इसके लक्षणों को जानकर शुगर लेवल कंट्रोल करें। तो चलिए जानते हैं कि शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर क्या-क्या संकेत मिलते हैं।

शुगर लेवल बढ़ने के संकेत

1. त्वचा में झूर्झियां - समय से पहले चेहरे पर झूर्झियों का पड़ना शुगर लेवल बढ़ने का संकेत होता है। इसके



साथ-साथ चेहरे पर दाग-धब्बे, मुँहासे और लाल धब्बे पड़ने लगते हैं।

2. लो एनर्जी - शरीर में शुगर बढ़ने पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। दरअसल शुगर शरीर की सारी ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे आपको थकान महसूस होने लगती है। इससे आप थोड़ी दूर चलने या कोई भी काम करके थक जाते हैं।

3. सूजन - शरीर में शुगर बढ़ने पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसके कारण खाना खाने के बाद पेट में दर्द, गैस, पेट का फूलन और पेट में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

4. बार-बार बीमार पड़ना - खून में शुगर लेवल ज्यादा हो जाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। जिससे बार-बार बीमार पड़ना या चोट का कई दिनों तक ठीक न होना और



ज्यादा यूरिन आना की प्रॉब्लम हो जाती है।

5. वजन बढ़ना - शरीर शुगर को ऊर्जा में बदल नहीं पाता, जिसके कारण पेट या कमर के आसापस चबीं इकट्ठी हो जाती हैं। इसकी के कारण शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है।

6. कमजोर इम्यून सिस्टम - इम्यून सिस्टम का 70% हिस्सा शरीर से बैक्टीरिया को निकालने का काम करता है लेकिन शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर यह ठीक से काम नहीं करता। इसी के कारण आपको कब्ज और छोटी-मोटी पेट संबंधित समस्याएं होती रहती हैं।

7. अनिद्रा - खोजन में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर आपको ठीक से नींद नहीं आती है। इसके अलावा रोजाना अधिक मात्रा में शुगर का सेवन अनिद्रा की समस्या भी पैदा कर सकता है।



काले चने में शहद मिलाकर खाने से मिलेंगे ये फायदे

काले चने का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। काबोर्डिंग, प्रोटीन, कैलिशम, आयरन और विटामिन के गुणों से भरपूर काले चने को भिंगो कर रोजाना खाने से कई बीमारियां दूर रोती हैं। वैसे तो भिंगे हुए चने खाने से कई फायदे होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें शहद मिलाकर खाने से इसके फायदे और भिंगे हुए चने खाने की कमी पूरी हो जाती है।

4. खून की कमी

चने और शहद दोनों में ही भरपूर आयरन होता है इसलिए इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है।

5. मजबूत हड्डियां

काले चने चबाने से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे दांतों के साथ हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा इससे आपको बुडापे में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

6. डायबिटीज

सुबह इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखता है, जोकि डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम का खतरा टल जाता है।

2. किडनी प्रॉब्लम

रोजाना इसका सेवन बॉडी के टॉक्सिन्स दूर करता है। इससे आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है।

3. कठा की समस्या

नियंत्रित कर लेते हैं। सही खानपान में अनाज, दाल, फल और सब्जियां, कम फैट वाला दुध, चीनी नमक के साथ रिफाइंड चीजों का सीमित प्रयोग कर मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही डाईट की अवस्था में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सबसे सुरक्षित पौधों पर आधारित प्रोटीन होता है। क्योंकि यह बेहतर पोषण के साथ बहुत कम कैलोरी देता है।

जिन्हा सेठ बताती हैं। सेहतमंद डाईट के साथ मोटापे पर शारीरिक सक्रियता बहुत जरूरी है। और हम ऐसे तरीके भी अपना सकते हैं, जो प्रभाव दिखाना सुनिश्चित करें। इसमें फूड सप्लीमेंट ऐसा ही एक तरीका है। यह ना सिर्फ सही पोषण प्रदान करता है। साथ ही वजन जैसी समस्या को रोकने में मदद भी करता है। इसे लेने के लिए फैट वाले न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।

पौधों पर आधारित प्रोटीन सप्लीमेंट ज्यादा बेहतर विकल्प है। क्योंकि इसे पचाने में आसानी होती है। जरूरी अमिनो ऐसिड मॉडल पी डी सी ए ए एस स्कोप फैट व कोलेस्ट्रोल की मात्रा कम और लेक्टोस नहीं होता। भारत में मोटापा ऐसी महामारी बनता जा रहा है, जो एक बड़ी जनसंख्या को अपनी चेपेट में ले रहा है, जिसे दूर करने के लिए अपने सेहत के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी।

मोटापे से जूझता भारत तीसरे स्थान पर



दुनिया भर में मोटापा ज्यादातर लोगों के स्वास्थ्य को चुनौती दे रहा है। जिसमें भारत को वर्ल्ड ओवेसिटी फेडरेशन की एक सर्वे रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर अंकित गया है। खास कर भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के मोटापे पर नजर अंदाज किया जाता है। साल 2025 तक 4.83 करोड़ भारतीयों के मोटापे से ग्रासित होने का पूवार्नुमान है। खासकर महिलाओं में मोटापे पर जीवनशैली से जुड़ी अस समस्या को लोगों के स्वास्थ्य के रूप में अनदेखा किया जा रहा है।

मुंबई के जानेमानी डायटीशियन जिम्मा सेठ बताती हैं। यह एक चिंता का विषय है। लगातार पोषक आहार और शारीरिक गतिविधियों में सुधार के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के बावजूद महिलाओं और अन्य लोगों में यह लगातार बढ़ता जा रहा है। सेहतमंद जीवन के लिए इसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक हो गया है। जिसमें प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के मोटापे दिल की बिमारी से लेकर गर्भधारण तक में दिक्कत ला सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उर्जा का असंतुलन एंडोकाइन मेडिकल स्थितियां और दवाईयों की वजह से भी मोटापा हो सकता है। कुछ लोगों का दुसरों के, मुकाबले बहुत तेजी से मोटापा बढ़

जाता है। यह समय पर नियंत्रण जरूरी बन गया है। जिसके लिए बहुत से लोग स्वस्थ खानपान और सक्रिय रहकर वजन को



कभी ईद कभी दीवाली से कटा शहनाज गिल का पता?

सलमान खान और शहनाज गिल को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही जिन पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल है। इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है ये तो कई मौकों पर देखने को मिला। कभी सलमान, शहनाज को गले लगाकर रोते रिखाई दिए तो कभी भीड़ में इप्पोर्ट्स देते हुए नजर आये। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स सामने आई है उनके मुताबिक अब सलमान और शहनाज के बीच कुछ अनबन चल रही है। यहाँ तक कि सलमान की फिल्म 'कभी ईद कभी दीवाली' से भी शहनाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दूरअस्त, सलमान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'कभी ईद कभी दीवाली' की शूटिंग में बिजी हैं। ये फिल्म पहले इस बात को लेकर खूब चर्चा में रही कि सलमान की इस फिल्म से उनकी जीजा आयुष शर्मा को किन्हीं कारणों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब ये फिल्म शहनाज गिल को लेकर कई दिनों से चर्चा में हैं। इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि शहनाज गिल को सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दीवाली से निकाल दिया गया है। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स में इस खबर की सच्चाई सामने आई है। ना सिर्फ फिल्म से निकाले जाने को लेकर बल्कि शहनाज ने जो सलमान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया है उसकी वर्चाओं ने भी सुर्खियां बढ़ाव दी हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने इन सब रिपोर्ट्स का खंडन किया है। रिपोर्ट की मानें तो ये सब अफवाह हैं।



सोनम कपूर के इस जवाब ने उड़ाए सबके होश

करण जोहर का पॉपलुर थैट शो 'कॉफी विद करण 7' लोगों के एक्साइटमेंट लेवल को अपने हर एक एपिसोड के साथ बढ़ा रहा है। 'कॉफी विद करण' में फिल्मी सितारों के पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों को जानने में लोगों को काफी मजा आता है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में एकत्र आमिर खन करीना कपूर खान के साथ पहुंचे थे। इस एपिसोड को लोगों ने खूब पसंद किया। आमिर और करीना के बाद शो के रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड में सोनम कपूर और अर्जुन कपूर की जोड़ी आने वाली है, जिसका फैस बेस्टी से इंतजार कर रहे हैं। 'कॉफी विद करण 7' के अपक्रिया एपिसोड में सोनम कपूर और अर्जुन कपूर पहली बार एक साथ आने वाले हैं। इससे पहले भी दोनों शो में आ चुके हैं लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि यह भाई बहन की जोड़ी एक साथ शो में आने वाली है। हाल ही में 'कॉफी विद करण 7' के अपक्रिया एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें सोनम कपूर और अर्जुन कपूर शो के होस्ट करण जोहर के साथ काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रोमो को देखकर तो लगता है कि सोनम अपने भाई को लेकर कुछ जबरजस्त खुलासे करने वाली है। करण जोहर ने अपने इंस्टाग्राम पर शो के अपक्रिया एपिसोड का प्रोमो शेयर किया है, जो काफी मजेदार और धमाकेदार लग रहा है। इस दौरान सोनम अर्जुन को लेकर ऐसी बात कहती है, जिसे सुनकर अर्जुन के साथ करण भी हैरान हो जाते हैं। सोनम कपूर एक के बाद एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर अर्जुन भी कहने लगते हैं कि लगता है शो पर उन्हें सोनम की ओर से ट्रोल होने के लिए बुलाया गया है।



जाह्वी कपूर ने इस वजह से खुद को बताया भाग्यशाली

बॉलीवुड एकदेश जाह्वी कपूर इस समय की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। एकदेश की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं जाह्वी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। फैंस भी सोशल मीडिया पर एकदेश की हर फोटो और वीडियो को खूब पसंद करते हैं। हाल ही में जाह्वी में अपने और अर्जुन कपूर के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान जाह्वी ने अब तक के सबसे खास रक्षा बंधन की यादें भी शेयर की। बता दें कि अर्जुन और उनकी बहन अंशुला कपूर बोनी कपूर की फर्स्ट वाइफ मोना के बच्चे हैं। वहीं जाह्वी और खुशी दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटियां हैं, जिनसे बोनी ने साल 1996 में शादी की थी। साल 2018 में श्रीदेवी के असामिक निधन के बाद बोनी कपूर के चारों बच्चों के बीच बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई है। जाह्वी कपूर ने अपनी फैमली और रक्षा बंधन के बारे में खुलकर बात की। एकदेश ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार उनके लिए सबसे स्पेशल रक्षाबंधन वह था जब उन्होंने अर्जुन को राखी बांधी थी। हालांकि इस बात को ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस बीतीमें उन्होंने कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें अर्जुन कपूर जैसा भाई मिला है।

